

स्मार्थ हलचल

► नए सत्र के बीच भाषा बदलना बच्चों के लिए परेशानी

क्लास 6 के बच्चों पर भी लागू नहीं होगा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को दिया निर्देश, वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह ही इस नीति के तहत छूट दी जाए

● नई दिल्ली



क्लास 6 में पहुंचते ही बच्चों के लिए पढ़ाई का एक नया दौर शुरू होता है लेकिन इस बार कुछ छात्रों के सामने कितानों और नए विषयों के साथ भाषा बदलने की चिंता भी दिखाई दे रही है। सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह ही इस नीति के तहत छूट दी जाए। दरअसल, इसे लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 2026-27 के सत्र से कक्षा 6 में तीन भाषाओं की व्यवस्था लागू की गई। कई स्कूलों और याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ

छात्र पहले से दूसरी भाषाएं पढ़ रहे हैं और अब उनसे भाषा बदलने को कहा जा रहा है। ऐसे में नए सत्र के बीच भाषा बदलना बच्चों के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसी परेशानी पर ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को अनावश्यक कठिनाई में डालने के बजाय उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए।

आखिर क्या है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी विवाद

सीबीएसई की नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत तीन भाषाओं की पढ़ाई से जुड़ी है। कक्षा 6 से छात्रों के लिए आर1, आर2 और आर3 के तहत तीन भाषाओं की व्यवस्था लागू की जा रही है। सीबीएसई के दिशानिर्देशों में कम से कम दो भारतीय भाषाओं को शामिल करने की बात कही गई है। विवाद तब शुरू हुआ जब मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र में लागू की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कई बच्चे चौथी कक्षा से ही अपनी पसंद की भाषाएं पढ़ रहे हैं। ऐसे में कक्षा 6 में अचानक भाषा बदलने से उन्हें परेशानी हो सकती है। सुनवाई के दौरान कितानों का मुद्दा भी सामने आया है। सरकार की ओर से कहा गया कि कितानें उपलब्ध हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कितानें ऑनलाइन उपलब्ध होने और बच्चों के पास उनकी भौतिक प्रतियां होने में अंतर है। सीबीएसई ने अपने मई के आधिकारिक सत्र में कहा था कि निर्धारित भाषाओं की आर3 पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी और सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की योजना है।

बच्चों को सुविधा चाहिए

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाकर उन स्कूलों और याचिकाकर्ताओं से बात की जाए, जो इस व्यवस्था को लेकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। वहीं, वरिष्ठ अधिकृत गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि अब किसी और समिति की जरूरत नहीं है और इस मामले में स्पष्ट फैसला लिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट बच्चों को मुश्किल में डालने के बजाय उन्हें सुविधा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को भी वही राहत दी जानी चाहिए जो कक्षा 7 के छात्रों को मिली है।

अब बिजली बिल में जुड़ सकता है ट्रैफिक चालान

कोर्ट ने कहा— सिर्फ ई-चालान जारी करते रहना काफी नहीं

● नई दिल्ली / आरएनएन

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान की वसूली को लेकर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुझाव



दिया कि अगर लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं तो इसकी वसूली के लिए बिजली बिल जैसे दूसरे सरकारी बकायों के साथ रकम जोड़ने जैसे तरीकों पर विचार लिया जा सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करते रहना काफी नहीं है।

पुलिस हजारों और लाखों ई-चालान जारी कर सकती है। लेकिन असली सवाल इन चालानों पर लगाए गए जुर्मानों की वसूली का है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-चालान के करीब 45000 करोड़ रुपये वसूलने हैं। इनमें से अब तक करीब 25000 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अधिकारियों को जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा।

यूएस स्पेशल ड्रग्स पर नहीं लगाएगा टैरिफ

वॉशिंगटन, आरएनएन। अमेरिका ने भारत समेत 20 देशों से आयातित कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनके संबंधित इंफ्रीडिपेंडेंट्स पर कोई एड वैलोरम टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस में ये जानकारी दी गई है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब वॉशिंगटन 29 सितंबर से कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट और उनसे जुड़े इंफ्रीडिपेंडेंट्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के के अनुसार, यूएस भारत और 19 अन्य देशों से आयातित कुछ खास दवाओं और उनसे जुड़े इंफ्रीडिपेंडेंट्स पर कोई एड वैलोरम (मूल्य-आधारित) टैरिफ नहीं लगाएगा। नोटिस के अनुसार, जीरो प्रतिशत टैरिफ की दर उन प्रोडक्ट्स पर लागू होगी, जिनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज, बाइपसन के इलाज, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबायोटिक-ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाओं में होता है।

2000 से ज्यादा यूपीआई वाले चार्ज पर रोक लगाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बोला— यह टैक्स नहीं, सीजेआई की बेंच ने पूछा— फिर ये क्या है, जल्द हलफनामा दें

● नई दिल्ली



सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ खास यूपीआई पर्सनल-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाना है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 से रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब भी मांगा है। केंद्र ने

सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 प्रतिशत लोग इससे छूट के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) समेत सभी पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।

एमडीआर की रकम का बंटवारा

टैक्स है, न सेस और न ही कोई सरचार्ज। यह दरअसल उस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च है, जिसे बैंक और फिनटेक कंपनियां संचालती हैं। कुल एकत्रित एमडीआर रकम का 40 प्रतिशत हिस्सा ग्राहक के उस बैंक को जाता है, जहां से पैसा कटता है। इसके बाद 30 प्रतिशत रकम पेमेंट गेटवे को, 20 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई सर्विस देने वाले मोबाइल ऐप को और बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई ऐप के स्पॉन्सर बैंक को दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मकसद बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को निर्बाध सेवाएं देने के योग्य बनाए रखना है।

व्यापारियों से वसूला जाने वाला एमडीआर न तो कोई टैक्स है, न सेस और न ही कोई सरचार्ज। यह दरअसल उस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च है, जिसे बैंक और फिनटेक कंपनियां संचालती हैं। कुल एकत्रित एमडीआर रकम का 40 प्रतिशत हिस्सा ग्राहक के उस बैंक को जाता है, जहां से पैसा कटता है। इसके बाद 30 प्रतिशत रकम पेमेंट गेटवे को, 20 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई सर्विस देने वाले मोबाइल ऐप को और बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई ऐप के स्पॉन्सर बैंक को दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मकसद बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को निर्बाध सेवाएं देने के योग्य बनाए रखना है।

नई पारी

सचिन ने चैटजीपीटी से प्लान की फैमिली ट्रिप, कहा— मुझे जानना है एआई के साथ क्या-क्या कर सकता हूं

अब चैटजीपीटी की पिच पर उतरे क्रिकेट के भगवान

● मुंबई

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अब तकनीक (एआई) की दुनिया से जुड़ गए हैं। उन्होंने एआई कंपनी ओपनएआई के साथ साझेदारी की है। तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट करके अपने और ओपन एआई के बीच हुई अपनी नई पार्टनरशिप की घोषणा की है।



एक्स पोस्ट में वीडियो शेयर की है। इसमें वे एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा मैं ओपनएआई के साथ अपनी इस साझेदारी की घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित हूं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने अपने परिवार के साथ ट्रिप पर जाने के लिए चैटजीपीटी के साथ मिलकर प्लानिंग की। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि वे उनको हमेशा से नई चीजें जानने की उत्सुकता

चैटजीपीटी ने 10 सवालों में पहचान लिया सचिन को

पार्टनरशिप की घोषणा के साथ तेंदुलकर ने एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें उन्होंने चैटजीपीटी को एक मजेदार चुनौती दी। उन्होंने एआई चैटबॉट से कहा कि वह अधिकतम 10 सवाल पूछकर उनकी पहचान करे। चैटजीपीटी ने तय सीमा के भीतर यह पहचान लिया कि सामने सचिन तेंदुलकर हैं। यह छोट्टा सा प्रयोग उनकी नई पार्टनरशिप के मुख्य आइडिया को भी दिखाता है कि कैसे एआई का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने, चीजों को एक्सप्लोर करने और रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

टीएमसी विवाद 4 महीने में सुलझाए चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी छह महीने की मोहलत

● नई दिल्ली / आरएनएन

नाम और निशान को लेकर चल रहा है विवाद

टीएमसी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह फूल और घास को लेकर चल रहा कानूनी विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में चार महीने के भीतर अपना आखिरी फैसला सुनाए।

अदालत ने सभी आयोग को निर्देश दिया है कि वो चार सप्ताह के भीतर अपनी सभी लिखित दलीलें और जरूरी दस्तावेज पूरी कर लें। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही दलीलें दाखिल करने की ये समय-सीमा खत्म होगी, उसके ठीक बाद चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न आदेश के पैरा 15 के तहत इस पूरे विवाद पर तीन महीने के भीतर अपना आखिरी फैसला देना होगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि ये मामला बेहद जटिल प्रकृति का है, इसलिए इस पर सही फैसला लेने के लिए आयोग को कम से कम छह महीने का समय चाहिए। आयोग की तरफ से ये भी हवाला दिया गया कि आने वाले दिनों में देश के पांच अलग-अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा काम है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत से SAR पर रोक की मांग

2000 जाने-माने नागरिकों ने सीजेआई को लिखा खुला पत्र

पत्र में ईसी पर ईसीआईनेट और फॉर्म 6 में बिना वैधानिक अनुमति बदलाव करने के आरोप लगाए

● नई दिल्ली

देश के 2,000 से अधिक जाने-माने नागरिकों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर की वैधता और उसकी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा पूरी होने और कोर्ट का फैसला आने तक इस पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई है।

चिट्ठी लिखने वालों ने सीजेआई से इस गंभीर मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील



की है। इन नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह चुनाव आयोग के आचरण और उसकी भूमिका पर स्वतः संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करे।

आंतरिक मतभेद का दिया हवाला

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग के भीतर भी आंतरिक मतभेद हैं। उनके अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संघ और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार उन फैसलों पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी, जो उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिए गए थे। इन नागरिकों ने मतदाता सुविधों से बढ़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और सॉफ्टवेयर लॉक्स की वजह से स्थानीय अधिकारियों को आ रही तकनीकी दिक्कतों की कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच और ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म के व्यापक ऑडिट की मांग की है।

हस्ताक्षर करने वाले नागरिकों ने कथित आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग के भीतर भी आंतरिक मतभेद हैं। उनके अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संघ और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार उन फैसलों पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी, जो उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिए गए थे। इन नागरिकों ने मतदाता सुविधों से बढ़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और सॉफ्टवेयर लॉक्स की वजह से स्थानीय अधिकारियों को आ रही तकनीकी दिक्कतों की कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच और ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म के व्यापक ऑडिट की मांग की है।

दिल्ली में बिना पीयूसी अब नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी

● नई दिल्ली / आरएनएन

सर्दियों की शुरुआत से काफी पहले ही दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्टिव हो गई है। सोमवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब राजधानी में पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण और यातायात वाले स्थानों का निरीक्षण करेंगी। इन फैसलों को 1 नवंबर से राजधानी में लागू किया जाएगा। दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से पार्किंग चार्ज डबल करने का फैसला किया।

एक नवंबर से पार्किंग चार्ज डबल

जहाजपुर पालिका की पहली सभा में गूंजा शहर के विकास का एजेंडा, पार्षदों ने खोली समस्याओं की पोटली...

सफाई, बिजली-पानी से लेकर आवारा गोवंश, सीसीटीवी, एम्बुलेंस और बजरी तक के मुद्दे उठे, त्योहारों से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर

स्मार्ट हलचल

अलकेश पारीक जहाजपुर। नगर पालिका बोर्ड के गठन के बाद पहली साधारण सभा की बैठक सोमवार को विधायक गोपीचंद मीणा एवं पालिका अध्यक्ष अलकेश वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास, साफ-सफाई, बिजली-पानी, नालियों, रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात रखी। पहली ही बैठक में पार्षदों ने वार्डों की जमीनी समस्याओं को सामने रखते हुए पालिका प्रशासन से उनके शीघ्र समाधान की मांग की। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि नए पालिका बोर्ड के सामने जहाजपुर के विकास को नई गति देने की बड़ी जिम्मेदारी है। शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ स्वच्छता व्यवस्था, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों और



घोषणाओं तक सीमित नहीं रहें, बल्कि उनका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। पालिका अध्यक्ष अलकेश वैष्णव ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य शहर के सभी 25 वार्डों में बिना भेदभाव विकास कार्य करवाना और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सभी पार्षदों के सहयोग से शहर की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष ने नगर पालिका के लिए टैक्सी वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी रखा।

को उपचार के लिए पहुंचाने के लिए नगर पालिका स्तर पर एम्बुलेंस खरीदने तथा शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग रखी। आवारा गोवंश और सस्ती बजरी का मुद्दा गरमाया पार्षद राधेश्याम बारेठ ने शहर में आवारा गोवंश से आमजन को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाते हुए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार को लिखित रूप से अवगत करवाकर नगरवासियों को सस्ती दर पर बजरी उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी रखा। उन्होंने कहा कि बजरी की उपलब्धता नहीं होने से आमजन को निर्माण कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। **कच्ची नालियों से मकानों को नुकसान का मामला** पार्षद तबस्सुम बी ने वार्ड में कच्ची नालियों की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि नालियों का पानी मकानों की नींव तक पहुंचने से भवनों को नुकसान का खतरा बना हुआ है।

उन्होंने कच्ची नालियों को हटाकर पक्की नालियों का निर्माण करवाने की मांग की। **नो चौक और बस स्टैंड बावड़ी क्षेत्र में सफाई की मांग** पार्षद योगेश चंद्र पत्रिया ने नो चौक एवं बस स्टैंड स्थित बावड़ी के बालाजी मंदिर के आसपास कचरा जमा नहीं होने देने की मांग रखी। उन्होंने पालिका कर्मचारियों के साथ आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाने और कचरा फैलाने वालों को पाबंद करने की बात कही। **25 वार्डों में समान विकास पर जोर** पार्षद अरविंद भुवालिया ने कहा कि नगर पालिका के सभी 25 वार्डों में साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया बोर्ड आमजन की सुविधाओं पर खरा उतरेगा और विकास के साथ शहर के सौंदर्यिकरण पर भी काम किया जाएगा। **सोलर लाइट और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग**

पार्षद सानिया खानम ने कस्बे में सोलर ऊर्जा आधारित लाइट लगाने की मांग रखी। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ पालिका स्तर पर कार्रवाई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता जताई। त्योहारों से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर बैठक में आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे करने पर भी चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में सफाई और प्रकाश व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहली साधारण सभा में सामने आए मुद्दों से साफ है कि नए पालिका बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की है। अब देखना होगा कि बैठक में उठे मुद्दे प्रस्तावों और चर्चाओं से आगे बढ़कर धरातल पर कब दिखाई देते हैं।

शहीद भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित



स्मार्ट हलचल

चंदेरिया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाउसिंग बोर्ड चंदेरिया में भगत सिंह ब्रिगेड के तत्वावधान में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन, संघर्ष एवं देशभक्ति के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को केले एवं पेन वितरित किए गए तथा अतिथियों द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिए गए। कार्यक्रम में चंचल कुमार खटौक, गोविंद सिंह लाखनोत, मोहित सुवालका, नवीन सोनी, पहलाद शर्मा एवं अमित रावण सहित विद्यालय के प्राचार्य हस्तीमल जी वीरवाल एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए विद्यालय प्रशासन एवं समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया।

70 वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में पापड़ी की बेटियों का जलवा, राज्य स्तर पर चयन

स्मार्ट हलचल

लाखेरी - 70वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में पापड़ी की छात्राओं ने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शील्ड एवं मेडल हासिल किए, वहीं खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ। राज्य स्तर पर चयन की खबर गांव पहुंचते ही खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय स्टाफ ने ढोल-नगाड़ों की धून पर उत्साह के साथ नाचते हुए चयनित खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ी की प्रधानाचार्य नीतू शर्मा ने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। विद्यालय स्टाफ की ओर से रेणू मीणा, बाबूलाल राठौर, ज्योति जैन कृष्ण कुमार को साफा बंधावकर स्वागत सम्मान विद्यालय परिवार की तरफ से उपप्रधानाचार्य राकेश कुमार ने सभी का आभार जताया व्यक्त किया कार्यक्रम में समस्त स्टाफ मौजूद रहे एवं खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।

माता जी का खेड़ा (भटेड़ा) में पंचायती राज चुनाव बहिष्कार की गूंज : 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े माता जी का खेड़ा के ग्रामीण

स्मार्ट हलचल

भटेड़ा भीलवाड़ा। जिले की बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की घरटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले माता जी का खेड़ा (भटेड़ा) गांव में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया है। ग्रामीण चांदमल कुमावत ने बताया कि आज के समय में हर गांवों में सड़क नाली बिजली पानी जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमारा गांव माताजी खेड़ा आज भी



मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हर बार चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मतदान खत्म होते ही गांव को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस बार ग्रामीणों ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक खेड़ा की राजस्व मांग पत्र पर जमीनी काम शुरू नहीं होता, तब तक क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी को कदम नहीं रखने

दिया जाएगा और न ही कोई ग्रामीण वोट डालने जाएगा। यह है ग्रामीणों की 12 प्रमुख मांगें, जिन पर अड़ा है पूरा गांव-ग्रामीणों ने गांव के समग्र विकास के लिए 12 सूत्रीय मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं: राजस्व व भूमि विस्तार: 'माताजी का खेड़ा' को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और गांव के आबादी क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर उसे दोगुना किया जाए।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार: स्थानीय विद्यालय में लंबे समय से स्थित चल रहे शिक्षकों के पदों को भरा जाए और छात्रों के लिए नए कमरों का निर्माण कराया जाए। सड़क व संपर्क मार्ग की बहाली: माताजी का खेड़ा से कूड़िया खुर्द जाने वाले रास्ते को तुरंत चालू किया जाए और माताजी का खेड़ा से कासोरिया सड़क का पक्का निर्माण करावाया जाए। पेयजल संकट का समाधान: क्षेत्र में पीने

के पानी की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए ऐतिहासिक 'माता जी की कुड़ी' का पुनः जीर्णोद्धार (मरम्मत) किया जाए। और पानी की मोटर लगाकर पीने का पानी धारा तक पहुंचाया जाए। गांव का ढांचागत विकास: गली मोहल्लों में पक्की सड़कों व नालियों का निर्माण हो, मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बड़े नालों का निर्माण किया जाए और रात के अंधेरे से मुक्ति के लिए पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक व सामाजिक सुविधाएं: ग्रामीणों के सामूहिक कार्यक्रमों के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो। इसके साथ ही रमजान घाट के रास्ते को दुरुस्त करने, दाह संस्कार स्थल पर टीन शेड लगाने व लोगों के बैठने के लिए सराय का निर्माण करने की मांग की गई है। साफ सफाई व कचरा प्रबंधन: गांव में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो और कचरा निस्तारण के

लिए एक स्थायी सिस्टम बनाया जाए। आश्विनियों से टूटना, अब आर-पार की लड़ाई स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, पानी, स्कूल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहां के लोगों को दशकों से संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार गांव को इस महापंचायत में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने एक स्वर में यह फैसला लिया है कि वे किसी भी खोखले आश्वासन के झांसे में नहीं आएंगे। जब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होता, तब तक चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा। ग्रामीणों के इस कड़े फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों और स्थानीय राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। चांदमल कुमावत दिलखुश कुम्हार अंकुश रामधन देवराज कैलाश रामराज वैष्णव धनराज कीर् ईश्वर गुर्जर जसवंत दरोगा राजू प्रजापत भागचंद वैष्णव सत्तू गुर्जर जमुनालाल वैष्णव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

निर्वाचन आयोग के घेराव में सुलक्षणा शर्मा ने जताया विरोध



महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल प्रयोग का आरोप, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठाई मांग

स्मार्ट हलचल

अनिल कुमार खोंची जयपुर। कांग्रेस की ओर से सोमवार को जयपुर में निर्वाचन आयोग के घेराव को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में नारेबाजी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकृत ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने और पानी की बौछार करने का आरोप लगाया गया। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव एवं अधिवक्ता सुलक्षणा शर्मा ने प्रदर्शन में शामिल होकर महिला कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हुए पुलिस बल प्रयोग को रोकने का प्रयास किया। सुलक्षणा शर्मा ने कहा कि चुनाव में कथित धांधलियों पर रोक लगनी चाहिए तथा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकृत ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग उठाई। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह और ब्यावर जिला अध्यक्ष इशिका जैन भी प्रदर्शन में शामिल रहीं।

'खुशी डांगी' ने 70वीं जिला स्तरीय एसजीएफआई स्कूल टूर्नामेंट में हासिल किया 'गोल्ड मेडल'

स्मार्ट हलचल

उदयपुर बड़गांव ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थुर में कक्षा 8 में अध्ययनरत 'खुशी डांगी' ने 70वीं जिला स्तरीय एसजीएफआई स्कूल योगानंद टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है एवं आगामी दिनांक 30.9.2026 को चुरु में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेगी। इस अवसर विद्यालय की प्रधानाचार्य रूफि पारिक व योगा कोच शुभम पुर्विया ने बताया कि पूरे गांव की निवासी खुशी डांगी पूर्व में भी योग की गतिविधि में एक वर्ल्ड रिकार्ड बना चुकी हैं एवं योग में आयोजित होने वाली कई प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। खुशी डांगी पिताजी योगेश डांगी खेली का कार्य करते हैं।

आयुर्वेद चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों से जानी उपचार की स्थिति

स्मार्ट हलचल

अनिल कुमार खोंची ब्यावर। निदेशालय आयुर्वेद विभाग

इस दौरान उन्होंने औषधियों की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाओं एवं चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ककवानी ने औषधि वितरण कक्ष में दवाओं की आपूर्ति एवं उपलब्धता की जानकारी ली तथा धनवंतरी औषध उद्यान का अवलोकन किया। इंडोर वार्ड में भर्ती मरीजों से संवाद कर उपचार एवं चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पंचकर्म कक्ष एवं ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर बायोवेस्ट मैनेजमेंट और अग्निशमन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही रत्ना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के तहत उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों की जानकारी ली। अतिरिक्त निदेशक ने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए अर्श-भगन्दर एवं पंचकर्म चिकित्सा सेवाओं के साथ रत्ना एवं रूयोजना का अधिकधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। चिकित्सालय प्रभारी डॉ. पारस चौहान ने बताया कि भर्ती मरीजों के लिए पर्याप्त औषधियां उपलब्ध हैं और दोनों समय निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। रूयोजना के प्रभावी संचालन के लिए नवीन फर्नीचर, पलंग, अग्निशमन उपकरण, पंचकर्म रथ एवं शस्त्र उपलब्ध करवाए गए हैं। चिकित्सालय में क्षारसूत्र निर्माण के लिए क्षारसूत्र कैबिनेट भी उपलब्ध करवाई गई है।

70वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में पापड़ी की बेटियों का जलवा, राज्य स्तर पर चयन

स्मार्ट हलचल

लाखेरी - 70वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में पापड़ी की छात्राओं ने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शील्ड एवं मेडल हासिल किए, वहीं खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ। राज्य स्तर पर चयन की खबर गांव पहुंचते ही खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय स्टाफ ने ढोल-नगाड़ों की धून पर उत्साह के साथ नाचते हुए चयनित खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ी की प्रधानाचार्य नीतू शर्मा ने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। विद्यालय स्टाफ की ओर से रेणू मीणा, बाबूलाल राठौर, ज्योति जैन कृष्ण कुमार को साफा बंधावकर स्वागत सम्मान विद्यालय परिवार की तरफ से उपप्रधानाचार्य राकेश कुमार ने सभी का आभार जताया व्यक्त किया कार्यक्रम में समस्त स्टाफ मौजूद रहे एवं खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।



